बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 23 ● अंक: 209 ● नई दिल्ली ● बुधवार 20 अगस्त 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन
बी-2/370, सुल्तानपुरी
दिल्ली-86

अंतरिक्ष मिशन को लेकर भाजपा का कांग्रेस पर हमला

नई दिल्ली । लोकसभा की कार्यवाही मंगलवार को हंगामेदार रही। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर भारत के अंतरिक्ष मिशन को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी, तब विदेशी ताकतों के इशारे पर भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को कमजोर करने की कोशिश की गई। इस बीच सरकार ने सदन में बताया कि 31 जुलाई तक 12 प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजनाओं के तहत 21,689 करोड़ रुपये का वितरण किया जा चुका है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि कांग्रेस ने विदेशी देशों जैसे अमेरिका, चीन और पाकिस्तान के कहने पर भारत के स्पेस मिशन को कमजोर किया। उन्होंने दावा किया कि केरल के प्रसिद्ध इसरो वैज्ञानिक नंबी नारायणन को 1994 में गलत तरीके से गिरफ्तार कराया गया। इस साजिश से भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को बड़ी क्षति हुई। दुबे ने कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती कि इस विषय पर सदन में चर्चा हो।

घुटनों तक पानी में उतरीं सीएम रेखा गुप्ता, लोगों से मिलकर बोलीं- दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति नहीं

नई दिल्ली ।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मंगलवार को बाढ़ पीड़ितों से मिलने राजधानी के यमुना बाजार इलाके में पहुंचीं. कुछ देर बात की, उसके बाद अचानक मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने जूते उतारे और बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए घुटने तक पानी में उतर गईं. ये देखकर उत्तरी दिल्ली के डीएम और दूसरे अधिकारी भी हैरान रह गए.

लोगों से बात कर सीएम बोलीं- स्थिति नियंत्रण में

मुख्यमंत्री ने यमुना बाजार की छोटी-बड़ी गलियों में करीब तीस मिनट तक लोगों से बात करके उनकी परेशानियां जानीं. फिर लौटकर मीडिया से बात करते हुए कहा कि स्थिति नियंत्रण में है. यमुना का जलस्तर मंगलवार सुबह 206 मीटर को छूने वाला था. इसकी वजह से यहां तक पानी आया है. लेकिन उसके बाद अधिक पानी नहीं आया,

ये अच्छी बात है.

आज-कल में उतर जाएगा पानी: सीएम

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि मैंने नियंत्रण कक्ष में भी देखा है. पानी जैसे आ रहा है, वैसे ही आगे निकल जा रहा है. पानी रुकने जैसा कुछ नहीं है. ये राजधानी का सबसे निचला इलाका है. ये यमुना बाढ़ क्षेत्र है, जहां मकान बने हुए हैं. मुझे लगता है कि पानी आज-कल में उतर जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने लोगों से निवेदन किया था कि वे अपने घरों को खाली कर दें, लेकिन ये लोग शिफ्ट नहीं हुए. अभी बस यहां बिजली बंद होने की दिक्कत है. इसलिए हमने सौर ऊर्जा से संचालित फ्लड लाइट्स की व्यवस्था की है ताकि रात में कोई समस्या न हो.

खतरे के निशान से ऊपर बह रही यमुना

हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है. इसके चलते राजधानी में निचले इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है. दिल्ली के पुराने रेलवे पुल पर यमुना नदी का जलस्तर सोमवार देर शाम को 206 मीटर तक छू गया था, जबकि खतरे का निशान 205.33 मीटर पर है. इसी के चलते बाढ़ एवं राहत का काम तेजी से करने के निर्देश दिए गए हैं. हालांकि अन्य इलाकों में यमुना के पानी से कोई खतरा नहीं है.

यमुना पर तीनों बैराज के गेट खोले गए

दिल्ली में यमुना की लंबाई करीब 22 किलोमीटर है. नदी के ऊपर वजीराबाद, ढ़ूंढ़ाह और ओखला में तीन बैराज हैं. 2023 में ढ़ूंढ़ाह के बैराज के पांच गेट न खुलने की वजह से यमुना का पानी आसपास के इलाकों में घुसने लगा था. इससे कई इलाके जलमग्न हो गए थे.

जांच से बाद में पता चला कि ढ़ूंढ़ाह बैराज के गेट के रखरखाव की कमी के कारण नहीं खुल पाए थे. इस मामले में हरियाणा सरकार ने इंजीनियर समेत चार लोगों को सस्पेंड भी किया था. अभी हाल में दिल्ली सरकार ने हरियाणा सरकार को पत्र लिखकर ढ़ूंढ़ाह बैराज के रखरखाव का जिम्मा उसे सौंपने की मांग दोहराई थी.

आवारा कुत्तों को पकड़ने गई एमसीडी की टीम पर हमला, एफआईआर दर्ज

नई दिल्ली । पुलिस ने मंगलवार को बताया कि लगभग 15-20 लोगों के एक समूह ने रोहिणी में आवारा कुत्तों को पकड़ने के अभियान के दौरान दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के कर्मचारियों के साथ कथित तौर पर मारपीट की। पुलिस के अनुसार, इस समूह ने एमसीडी कर्मचारियों पर हमला किया, दो पकड़े गए कुत्तों को छुड़ा लिया और एमसीडी वाहन में तोड़फोड़ की, उसकी खिड़कियाँ तोड़ दीं और रजिस्टर व लॉगबुक चुरा लीं। रोहिणी के डीसीपी राजीव रंजन ने कहा कि लगभग 15-20 तथाकथित कुत्ते प्रेमियों के एक समूह के खिलाफ कल शिकायत दर्ज की गई थी। उन्होंने कथित तौर पर आवारा कुत्तों को पकड़ने वाले एमसीडी वाहन में बाधा डाली, दो आवारा कुत्तों को छुड़ा लिया और एमसीडी कर्मचारियों पर हमला किया - इस घटना में तोड़फोड़ शामिल थी, जिसमें वाहन की खिड़कियाँ तोड़ना और रजिस्टर व लॉगबुक चुराना शामिल था।

उन्होंने आगे कहा कि लोक सेवक को उनके कर्तव्य निर्वहन में बाधा डालने और चोरी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले शुक्रवार को, 11 और 12 अगस्त को नई दिल्ली जिले में कई जगहों पर बिना पूर्व अनुमति के कुत्ता प्रेमियों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शनों के सिलसिले में चार प्राथमिकी दर्ज की गईं। पुलिस ने कहा कि जिन लोगों ने बार-बार अनुरोध के बावजूद विरोध स्थल छोड़ने से इनकार कर दिया, उन्हें हिरासत में लिया गया। कानून का उल्लंघन करने वाले सभी लोगों के खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह घटनाक्रम आवारा कुत्तों को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई के बीच सामने आया है। 11 अगस्त को, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद के सभी इलाकों को आवारा कुत्तों से मुक्त किया जाए, और इस मामले में कोई समझौता नहीं किया जाए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि पकड़े गए किसी भी जानवर को वापस सड़कों पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। गुरुवार (14 अगस्त) को, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को हटाकर उन्हें आश्रय गृहों में रखने के अपने 11 अगस्त के निर्देश पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि वह एक अलग पीठ के 11 अगस्त के फैसले पर अंतरिम आदेश पारित करेगी।

अमनदीप सिंह ढल्ल की चार्जशीट और समन आदेश को चुनौती

दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई को जारी किया नोटिस

नई दिल्ली । दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को व्यवसायी अमनदीप सिंह ढल्ल की याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया। इस याचिका में दिल्ली आबकारी नीति मामले में उनके खिलाफ दायर आरोपपत्र और समन आदेश को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा ने सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई 25 नवंबर को सूचीबद्ध की गई है। सीबीआई की ओर से विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) डीपी सिंह पेश हुए। सुनवाई के दौरान, सीबीआई ने याचिका की विचारणीयता को चुनौती दी थी। कहा गया था कि याचिकाकर्ता दो साल बाद उच्च न्यायालय आया है। यह याचिका खारिज नहीं की जाएगी। विशेष लोक अभियोजक डीपी सिंह ने दलील दी कि संज्ञान आदेश को चुनौती दी जा सकती थी। यह दो साल पहले लिया गया था। अब वे संज्ञान लेने के दो साल बाद निरस्तीकरण याचिका दायर करना चाहते हैं। ढल्ल ने अधिवक्ता आदित एस पुजारी के माध्यम से याचिका दायर की है। वकील ने दलील दी कि याचिका में आरोपपत्र और समन आदेश को चुनौती दी गई है, न कि प्राथमिकी को। यह तर्क दिया गया कि ढल्ल अन्य आरोपियों के साथ कथित साजिश का हिस्सा नहीं थे। वकील पुजारी ने आगे दलील दी कि 2023 में सीबीआई ने ढल्ल के खिलाफ एक पूरक आरोपपत्र दायर किया था। इसके बाद, संज्ञान लिया गया और समन जारी किए गए। जुलाई 2024 में जाँच पूरी हुई और एक पूरक आरोपपत्र दाखिल किया गया। फरवरी 2025 में, उन्होंने उन दस्तावेज़ों की एक सूची दाखिल की जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने आगे कहा कि हम स्थगन की माँग नहीं कर रहे हैं। अदालत ने सीबीआई से पूछा था, आपकी एकमात्र आपत्ति यह है कि समय सीमा समाप्त हो गई है? एजेंसी ने दलील दी थी कि यह दलील मान्य नहीं होगी। अदालत का दायरा सीमित है। यह मामला दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। इस मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य भी आरोपी हैं।

महरौली पुरातत्व पार्क में बने स्मारकों की निगरानी करे एएसआई, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने महरौली पुरातत्व पार्क में बने स्मारकों के पास नए निर्माण से जुड़ी याचिका पर बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को पार्क में बने स्मारकों की निगरानी पर विचार करना चाहिए। इनमें कथित तौर पर 700 साल पुरानी आशिक अल्लाह दरगाह और सूफी संत बाबा फरीद की चिल्लागाह भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट से महरौली या संजय वन में दरगाह और आसपास के अन्य ऐतिहासिक स्मारकों को ध्वस्त करने या हटाने से रोकने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत ने 28 फरवरी को आदेश दिया था कि हमारी अनुमति के बिना क्षेत्र में मौजूदा संरचनाओं में कोई निर्माण, परिवर्धन या परिवर्तन नहीं किया जाए। पीठ ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के वकील से पूछा कि आप इसे पहले क्यों ध्वस्त करना चाहते हैं? इस पर डीडीए के वकील ने कहा कि प्राधिकरण दरगाह के खिलाफ नहीं है, लेकिन आसपास कई अन्य अनधिकृत संरचनाएं बनी

हुई है। सवाल यह है कि इसका कितना हिस्सा संरक्षित स्मारक है और कितना हिस्सा अतिक्रमण है। पीठ ने कहा कि आगे कोई निर्माण कार्य नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन स्मारक को संरक्षित किया जाना चाहिए। हमारा संबंध केवल स्मारक से है। पीठ ने कहा कि हम यह कहते हुए इन अपीलों का निपटारा करते हैं कि एएसआई को मरम्मत, नवीनीकरण के मामले में संबंधित स्मारकों की देखरेख पर विचार करना चाहिए। मामले से अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि जिन स्मारकों को लेकर अपील की जा रही है, वह अतिक्रमण नहीं थे। स्मारक 12वीं शताब्दी से ही इस क्षेत्र में मौजूद हैं। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि संरचनाओं को केंद्रीय संरक्षित स्मारक नहीं माना गया है, फिर भी एएसआई उनकी मरम्मत और रखरखाव की निगरानी कर सकता है। डीडीए के वकील ने दलील दी कि प्राधिकरण का संबंध केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण करने वाले अनधिकृत ढांचों को गिराने से है। अपीलकर्ता ने पार्क के अंदर स्थित धार्मिक संरचनाओं को ध्वस्त होने से बचाने की मांग की।

इससे पहले एएसआई ने कहा था कि पुरातात्विक पार्क के अंदर स्थित दोनों संरचनाओं का धार्मिक महत्व है, क्योंकि मुस्लिम श्रद्धालु प्रतिदिन इन दरगाहों पर आते हैं। शेख शहीबुद्दीन (आशिक अल्लाह) की कब्र पर एक शिलालेख कहता है कि इसका निर्माण वर्ष 1317 ईस्वी में हुआ था। पुनर्स्थापना और संरक्षण के लिए किए गए संरचनात्मक बदलावों ने इस स्थान की ऐतिहासिकता को प्रभावित किया है। एएसआई ने दलील दी कि यह मकबरा पृथ्वीराज चौहान के गढ़ के करीब है और प्राचीन स्मारक व पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम के तहत 200 मीटर के नियामक क्षेत्र में आता है। इसके अनुसार, किसी भी मरम्मत, नवीनीकरण या निर्माण कार्य को सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत जमीर अहमद जुमलाना की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दिल्ली के महरौली पुरातत्व पार्क के अंदर सदियों पुरानी धार्मिक संरचनाओं के संरक्षण की मांग की गई थी, जिसमें 13वीं शताब्दी की आशिक अल्लाह दरगाह (1317 ईस्वी) और बाबा फरीद की चिल्लागाह शामिल हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उनकी ऐतिहासिकता का आकलन किए बिना अतिक्रमण हटाने के नाम पर संरचनाओं को ध्वस्त करने की योजना बनाई है। जुमलाना ने 8 फरवरी को दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था।

राहुल गांधी किसी हमले से नहीं डरते... एसआईआई विवाद के बीच प्रियंका गांधी की हुकांर

नई दिल्ली । कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने मंगलवार को चुनाव आयोग को वोट चोरी के विवादास्पद मुद्दे पर सफाई देने की कड़ी चुनौती दी और चुनाव आयोग पर जवाबदेही से बचने का आरोप लगाया। उन्होंने राहुल गांधी की बहादुरी की भी प्रशंसा की और कहा कि वह किसी भी हमले से विचलित नहीं होते और विचलित करने वाली परिस्थितियों के बावजूद पीछे नहीं हटेंगे। कांग्रेस सांसद ने संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए कहा, इस वोट चोरी मुद्दे पर, उन्हें (चुनाव आयोग) जनता को सच्चाई बतानी चाहिए। राहुल जी किसी हमले से नहीं डरते, सह लेंगे, सब कुछ और पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि वे राहुल जी द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए वे हलफनामे, नेहरू जी और इंदिरा जी के बारे में बात करने लगते हैं। चुनाव आयोग के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बढ़ते विरोध के बीच, कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को दोहराया कि विधानसभा और लोकसभा चुनावों में कथित वोट चोरी संविधान की हत्या है। उन्होंने कहा कि अगर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) इस तरह की चुनावी गड़बड़ी के जरिए गद्दी पर बैठते हैं तो लोकतंत्र को नुकसान होगा। यह कहते हुए कि पार्टी वोटों की हेराफेरी, चोरी और छेड़छाड़ के खिलाफ लोगों को आगाह करने के लिए माहौल बनाना चाहती है, खड़गे ने संसद के बाहर संवाददाताओं से कहा कि हमारी पार्टी का यह रुख है कि हम देश भर में वोटों की चोरी, हेराफेरी और छेड़छाड़ के खिलाफ माहौल बनाना चाहते हैं, कि लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि अगर वे इस तरह की चोरी करके गद्दी पर बैठते हैं, तो यह लोकतंत्र के लिए फायदेमंद नहीं है। यह संविधान की हत्या है। इससे पहले, आज, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने भारत के चुनाव आयोग और बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान पर लगे वोट चोरी के आरोपों के खिलाफ संसद भवन के बाहर अपना विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया। विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और अन्य प्रमुख नेता मौजूद रहे। चुनाव आयोग द्वारा बिहार में वोट चोरी के आरोपों और स्कूल पर स्पष्टीकरण देने के बाद से विरोध प्रदर्शन जारी है। चुनाव आयोग ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से चुनाव में धांधली के अपने दावों के सबूत के साथ एक हस्ताक्षरित हलफनामा जमा करने को भी कहा है।

चुनाव आयोग और विपक्षी दल

बिहार में चल रहे विशेष सघन मतदाता पुनरीक्षण (एसआईआर) पर जिस तरह देश की विपक्षी पार्टियों और चुनाव आयोग के बीच रस्साकसी शुरू हुई है उसका सीधा प्रभाव भारत के मतदाताओं पर पड़ रहा है। विपक्षी दल खासकर कांग्रेस पार्टी जिस तरह चुनाव आयोग को सीधे निशाने पर ले रही है और चुनाव आयोग उसका सख्त पलट जवाब दे रहा है, उससे निकलने वाले परिणाम भारत के लोकतन्त्र को भी प्रभावित किये बिना नहीं रह सकते। स्वतन्त्र भारत में यह पहला अवसर है जब विपक्षी राजनीतिक पार्टियां चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रही हैं और कह रही हैं कि आयोग सत्तारूढ़ दल के प्रभाव में काम कर रहा है। जरूरत इस बात की है कि एसआईआर पर विवाद जल्द से जल्द खत्म हो। मामला सर्वोच्च न्यायालय में भी चल रहा है जिसके बीच ही मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने मतदाता पुनरीक्षण के मुद्दे पर प्रेस कान्फ्रैंस कर डाली और कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी द्वारा लगाये गये आरोपों को झूठा बताया। श्री ज्ञानेश कुमार अच्छी तरह जानते हैं कि चुनाव आयोग को किसी भी राजनीतिक दल से किसी प्रकार का मतलब नहीं होता। इसलिए उनका यह बयान कि राहुल गांधी सात दिनों के भीतर अपनी शिकायत के साथ शपथ पत्र दाखिल करें अन्यथा लगाये गये झूठे आरोपों पर देश से माफी मांगें, पूरी तरह अवांछित है। वास्तव में ये शब्द कहते हुए श्री ज्ञानेश कुमार को यह ध्यान रखना चाहिए था कि श्री गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। उन्होंने कर्नाटक राज्य के एक विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में भारी संख्या में फर्जी मतदाताओं के होने की बात कही है। श्री गांधी ने चुनाव आयोग द्वारा दी गई मतदाता सूची में ही गड़बड़ी होने की बात सप्रमाण कही है। अतः चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि वह पूरे मामले की सघन जांच कराये। भारत के संसदीय लोकतन्त्र में ऐसे मौके कई बार आये हैं जब किसी राजनीतिक दल की लिखित शिकायत पर आयोग ने सख्त जांच कराई है। पिछले 79 वर्षों के भारत के इतिहास में ऐसा मौका पहली बार देखने को मिल रहा है जब मुख्य चुनाव आयुक्त किसी राजनेता से माफी मांगने के लिए कह रहा है और शपथ पत्र देने का निर्देश दे रहा है। यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि चुनाव आयोग की कारगुजारियों से सरकार का कोई मतलब नहीं है, चाहे वह सरकार किसी भी राजनीतिक दल की हो। हमारे संविधान निर्माताओं ने देश में चुनाव कराने की प्रक्रिया और इसके पूरे तन्त्र को इसी उद्देश्य से स्थापित किया था कि हर हालत में चुनाव आयोग बिना किसी लाग-लपेट और भेदभाव के देश के चुने हुए सदनों के चुनाव करायेगा और इसके लिए मतदाता मंडल का निर्माण करेगा। यह मतदाता मंडल 18 वर्ष से ऊपर के हर भारतीय नागरिक का होगा। इसका मतलब यही है कि चुनाव आयोग का मुख्य कार्य सर्वप्रथम ऐसी मतदाता सूची का निर्माण करना होगा जिसमें आलीशान मकान में रहने वाले व्यक्ति से लेकर सड़क पर ही सोने वाले व्यक्ति का नाम दर्ज होगा। इन सबके वोट की कीमत एक बराबर होगी। संविधान निर्माता डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसे राजनीतिक समानता की संज्ञा दी थी। यह समानता एक वोट के अधिकार से ही आयी जिसे महात्मा गांधी ने स्वयंभू मतदाता के रूप में निरुपित किया। लोकतन्त्र का असली मालिक यही मतदाता होता है। यह बेवजह नहीं है कि भारत में हर पांच साल बाद हर राजनीतिक दल का नेता जनता के बीच जाता है और कसम उठाता है कि यदि वह चुनाव जीतता है तो जनता या मतदाता का हुक्म बजायेगा। मतदाता बहुत सोच-समझ कर अपना वोट जब किसी राजनीतिक दल के प्रत्याशी को डालता है तो वह लोकतन्त्र का राजा होता है। अतः यदि मतदाता सूची से किसी भी भारत के नागरिक का नाम कट जाता है तो यह उसके साथ बेइमानी होती है। इसके उलट यदि मतदाता सूची में फर्जी नाम जुड़ जाते हैं तो यह लोकतन्त्र को प्रदूषित करते हैं। बिहार में अभी तक 65 लाख मतदाताओं के नाम काट दिये गये हैं जिनमें 22 लाख ऐसे नागरिक हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। मगर बहुत से मृत लोग जीवित पाये जा रहे हैं। इसे हम गफलत कहेंगे। चुनाव आयोग से अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसी गलती नहीं करेगा क्योंकि सूची बनाने का काम उसी का है। जहां तक शपथ पत्र का सवाल है तो खुद मुख्य चुनाव आयुक्त भी यह शपथ नहीं ले सकते कि उनके द्वारा बनाई गई सूची पूर्णतः त्रुटिहीन है। दरअसल चुनाव आयोग ऐसी संवैधानिक संस्था है जो भारत के पूरे लोकतन्त्र को अपने कन्धे पर ढोती है क्योंकि उसका कार्य समाप्त होने के बाद ही इस तन्त्र के तीन मुख्य खम्भे अपना कार्य करने में सक्षम हो पाते हैं। बेशक न्यायपालिका पूरी तरह स्वतन्त्र व अराजनैतिक होती है और यह देश में संविधान का शासन देखने के कर्तव्य से बन्धी होती है। जबकि कार्यपालिका व विधायिका चुनाव परिणामों पर मयस्सर होती हैं। इसी प्रकार चुनाव आयोग भी पूरी संवैधानिक शुचिता के साथ अपने कार्य को अंजाम देता है। मगर क्या कयामत है कि श्री ज्ञानेश कुमार फरमा रहे हैं कि राहुल गांधी देश से माफी मांगें। ऐसा करके वह उस लक्ष्मण रेखा को लांघ गये जो संविधान ने ही उनके लिए खींची है। समझने वाली बात यह है कि राजनीतिक दलों की पूरी व्यवस्था देखने का काम जब चुनाव आयोग करता है तो उसे संविधान ने कुछ न्यायिक अधिकार भी दिये हैं। इन अधिकारों के चलते वह सभी राजनीतिक दलों को एक समान देखने के धर्म से बन्धा होता है। उसके लिए सत्ता पक्ष या विपक्ष के कोई मायने नहीं होते। वह केवल राजनैतिक दल की हैसियत ही पहचानता है।

हमारे संविधान निर्माता इतनी खूबसूरत व्यवस्था करके गये हैं कि सभी राजनीतिक दलों की नकेल एक 'अराजनैतिक' संस्था चुनाव आयोग को दे दी। चुनाव आयोग सरकार का अंग न होते हुए भी देश में राजनीतिक प्रशासन प्रणाली की आधारशिला रखता है लेकिन विपक्ष व चुनाव आयोग की लागडांट अब सीधे जनता व चुनाव आयोग के बीच तनाव पैदा करता दिखता है। इस स्थिति को हर सूरत में टाला जाना चाहिए।

सम्पादकीय...

भारत के सोचने, समझने और कार्यशैली में कितना बड़ा अंतर आया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 12वीं बार राष्ट्र को संबोधित किया। पीएम के संबोधन में आत्मनिर्भर भारत की जो सुखद तस्वीर दिखाई दी, पीएम ने आत्मनिर्भर भारत को विकसित और सशक्त भारत की नींव बताया। प्रधानमंत्री मोदी लाल किले से 103 मिनट तक बोले। यह किसी भी प्रधानमंत्री का, लाल किले से अभी तक सबसे लंबा भाषण है। प्रधानमंत्री ने कई मुद्दों को छुआ और यह एक परंपरा रही है। उन्होंने देश के रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, तकनीक और कृषि जैसे प्रमुख क्षेत्रों में हुई उपलब्धियों को गिनाते हुए भारत की आत्मनिर्भर यात्रा का उल्लेख किया। अंतरिक्ष में भारत का स्टेशन बनाने की बात भी कही। हाल ही में अंतरिक्ष से यात्रा कर लौटे शुभांशु शुक्ला का भी प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया। प्रधानमंत्री के पूरे भाषण के एक- एक शब्द पर विचार करें तो इस बात का सहज आभास होता है कि पिछले एक दशक में भारत कितना बदला है। भारत के सोचने, समझने और कार्यशैली में कितना बड़ा अंतर आया है। पीएम ने जितनी भी घोषणाएं लाल किले की प्राचीर से कीं, वो सभी अहम हैं लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और सुखद घोषणा यह की कि साल के अंत तक हम 'मेड इन इंडिया' सेमीकंडक्टर चिप बनाने लगेंगे। यदि यह घोषणा जमीनी स्तर पर साकार हो जाए तो आने वाले 10-15 सालों में भारत वाकई 'सोने की चिड़िया' वाला देश बन सकता है। यह अतिशयोक्ति नहीं है, बल्कि वैश्विक वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के आकलन हैं। भारत एक व्यापक, विविध देश है, जनसंख्या 146 करोड़ से अधिक है, निवेश पर्याप्त है और सरकार की प्राथमिकता है, लिहाजा व्यापक स्तर पर 'चिप' का उत्पादन संभव है। हालांकि हम अभी चीन, अमेरिका, ताइवान सरीखे देशों से बहुत पीछे हैं। वे 'चिप्स क्रांति' के देश हैं, जबकि भारत अभी शोध के दौर में रहा है। दुनिया डिजिटल क्रांति के दूसरे चरण में प्रवेश कर रही है, जहां सेमीकंडक्टर और चिप निर्माण एक रणनीतिक ताकत बन चुके हैं लेकिन भारत अब भी तैयारियों के शुरुआती मोड़ पर खड़ा है। हालांकि गुजरात और बेंगलुरु में कुछ प्लांट लगाए गए हैं। स्टार्ट-अप भी काम कर रहे हैं लेकिन अभी राष्ट्रीय उत्पादन के लिहाज से हम पीछे हैं। चीन आज दुनिया की 'डिजिटल रीढ़' है। माइक्रो चिप से लेकर मोबाइल फोन और सर्वर तक, हर जगह उसकी उपस्थिति है। अब भारत के लिए चिप का राष्ट्रीय उत्पादन, विस्तार और रोजगार 'तकनीकी संप्रभुता' का सवाल है। भारत के पास प्रतिभाशाली इंजीनियर और डिजाइनर हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों के लिए 'चिप निर्माण' के सूत्रधार बने हैं। यदि प्रधानमंत्री मोदी अपनी घोषणा को साकार कराने और उसे निरंतरता देने में सफल रहे तो सेमीकंडक्टर चिप भारत के लिए 'तेल' साबित हो सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण और देशव्यापी घोषणा प्रधानमंत्री ने जीएसटी को लेकर की है। सरकार ने अपने प्रस्ताव जीएसटी परिषद को विचारार्थ भेज भी दिए हैं। जीएसटी के दायरे में 10 लाख से ज्यादा वस्तुएं हैं। उसकी स्लैब दरें 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी की जाती हैं तो यह देश के लिए वाकई 'दीपावली का तोहफा' होगा। ये वस्तुएं सस्ती हो सकती हैं-टूथ पाउडर, नमकीन, सूखे मेवे, टूथपेस्ट, साबुन, पेन किलर दवाएं, सब्जियां, कंडेंस्ड मिल्क, कुछ मोबाइल और कम्प्यूटर, सिलाई मशीन, प्रेशर कुकर, 1000 रुपए से ज्यादा के रेडीमेड कपड़े, 500-1000 रुपए की रेंज वाले जूते, बर्तन, ज्योमेट्री बॉक्स, नक्शे, कृषि मशीनरी, सोलर वाटर हीटर, पब्लिक वाहन, स्टोव, सीमेंट, फ्रिज, टीवी, एसी, वाशिंग मशीन आदि। जाहिर है कि आम आदमी को राहत मिलेगी। अब सिर्फ दो ही स्लैब होंगे-5 फीसदी और 18 फीसदी। जीएसटी के दायरे में आने वाली मक्खन, फ्रूट जूस आदि वस्तुएं भी सस्ती होंगी। सरकार का आकलन है कि जीएसटी की दरें घटाने से लघु, सूक्ष्म, मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) में नौकरियों के अवसर बढ़ेंगे, ठेका श्रमिक बढ़ेंगे, आम आदमी की खर्च योग्य आय भी बढ़ेगी। देश की अर्थव्यवस्था पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और जीडीपी 0.6 फीसदी से 0.7 फीसदी तक बढ़ सकती है। रोजगार देश की एक बुनियादी समस्या है। प्रधानमंत्री मोदी ने 1 लाख करोड़ रुपए की 'प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना' की घोषणा की है। दावा किया जा रहा है कि इससे करीब 3.5 करोड़ युवाओं को नौकरियां और रोजगार मिल सकेंगे। लाल किले से गर्व भरे भाव में प्रधानमंत्री मोदी ने 'ऑपरेशन सिंदूर' का जिक्र करते हुए कहा कि भारत अब अपनी सुरक्षा के लिए किसी और पर निर्भर नहीं है। 'ऑपरेशन सिंदूर' इसका सबसे सटीक उदाहरण है, जिसमें भारत ने स्वदेशी तकनीक और हथियारों के दम पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। देश ने स्वदेशी हथियार और टेक्नोलॉजी से खुद को इतना मजबूत बना लिया है कि किसी भी खतरे का जवाब तेजी से और अपने तरीके से दे सकता है। पीएम मोदी ने युवाओं से अपील की कि भारत को जेट इंजन जैसी उन्नत रक्षा तकनीक खुद बनानी चाहिए। लाल किले से धरती से लेकर आसमान तक का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। उन्होंने ऐलान किया कि भारत जल्द ही अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। उन्होंने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत अब सिर्फ अंतरिक्ष में मौजूद नहीं है, बल्कि नेतृत्व करने की स्थिति में है। 300 से ज्यादा भारतीय स्टार्ट-अप स्पेस टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट और एक्सप्लोरेशन पर काम कर रहे हैं, ये देश के अंतरिक्ष क्षेत्र को नए युग में ले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि किसानों को सशक्त बनाने के लिए अब उर्वरकों का उत्पादन देश में ही बढ़ाना जरूरी है। अभी भारत एक बड़ी मात्रा में उर्वरक आयात करता है जिससे खर्च भी बढ़ता है और आत्मनिर्भरता भी प्रभावित होती है। घरेलू उत्पादन से खाद्य सुरक्षा, किसान कल्याण और अर्थव्यवस्था तीनों को मजबूती मिलेगी। नागरिकों से अपील करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 'स्वदेशी' सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि गर्व की बात होनी चाहिए। उन्होंने दुकानदारों से अपील की कि वे अपनी दुकानों पर 'स्वदेशी' बोर्ड लगाएं और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दें। यह केवल एक अभियान नहीं, बल्कि आर्थिक आजादी की दिशा में जनभागीदारी है। वोकल फॉर लोकल का जिक्र इससे पहले भी कई बार प्रधानमंत्री कर चुके हैं। जिस तरह अमेरिका टैरिफ की धमकियां भारत को दे रहा है। ऐसे में हमें ज्यादा से ज्यादा सामान देश के कारीगरों द्वारा बनाया हुआ खरीदना चाहिए। इससे देश की आर्थिकी को तो बूस्ट मिलेगा ही, वहीं रोजगार का सृजन भी होगा। प्रधानमंत्री ने 'मिशन सुदर्शन चक्र' की शुरुआत की घोषणा की, जिसका मकसद भारत की रक्षा क्षमताओं को और मजबूत करना है।

कहां नाच रहे हो मि. मुनीर, कुछ होश है ?

सर्कस आप सब ने कभी न कभी देखा ही होगा, उसमें एक जोकर होता है। सीरियस एडवेंचर वाले कारनामों के बीच वह कुछ ऐसी हरकत करता है कि लोग हंस पड़ें। कुछ मनोरंजन हो जाए। आखिर तनाव भी आदमी कब तक झेले? अब आप सोचेंगे कि सर्कस के जोकर की याद मुझे क्यों आ गई? दरअसल पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष आसिम मुनीर साहब की एक हरकत ने मुझे जोकर की याद दिलाई है जो टैरिफ युद्ध के इस गंभीर माहौल में भारत पर हमले की शुरूआत पूरब से करने की बात कर रहे हैं। वैसे जोकर के किरदार के प्रति भी मेरे मन में बड़ा सम्मान है इसलिए मुनीर को जोकर कहने में भी संकोच हो रहा है। मुनीर की हालत बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी है। आपने देखा होगा कि बारात में कुछ लोग अचानक आकर नाचने लगते हैं, वे ऐसा दिखावा करते हैं जैसे दूल्हे के असली दोस्त वही हों। लोग उन पर पैसे लुटाने लगते हैं, उन्हें भ्रम हो जाता है कि वाकई वे दूल्हे के असली दोस्त हैं। मुनीर साहब की हालत कुछ ऐसी ही है, अरे जनाब यह तो ध्यान रखो कि कहां नाच रहे हो, किसके आगे नाच रहे हो, क्या बोल रहे हो, कुछ होश है क्या? वैसे आप इस बात पर आपत्ति जता सकते हैं कि मैंने मुनीर के आगे साहब शब्द क्यों लगाया। दरअसल उन्होंने पूरब से हमले की बात की है तो मुझे फिल्म पूरब और पश्चिम का गाना याद आ गया। है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। इसी गाने की एक पंक्ति है जिसमें प्यार निभाना आता है और ये पाकिस्तान तो भारत की ही औलाद है तो वहां के सेना अध्यक्ष को हमें सम्मान देते हुए साहब क्यों नहीं कहना चाहिए। वो लफ्ज़ों हो गया तो ये उसकी तकदीर। हमारी तासीर तो प्यार भरी ही होनी चाहिए। अमेरिका की धरती पर खड़े होकर बावले मुनीर जब हिंदुस्तान के पूरब पर हमले की बात रहे थे तो मैं आश्चर्यचकित था कि पाकिस्तान के पुराने पूर्वी हिस्से को क्या उन्हें याद नहीं आती? उसी पूर्वी हिस्से का नाम अब बंगलादेश है। मि. मुनीर, याद कर लेते कि 71 की जंग में पाकिस्तान को बचाने के लिए अमेरिका ने एक युद्धपोत भेजा था, इसके बावजूद इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के दो फाड़ कर दिए थे। हमारी फौज ने 94 हजार पाकिस्तानी फौजियों को सरेंडर कराया था। आपकी फौज अपना पूर्वी हिस्सा तो बचा नहीं सकी और भारत के पूर्वी हिस्से पर हमले की बात करते हो। चलो, कारगिल को ही याद कर लेते, मुशर्रफ ने तो बड़ी कुटिल व्यूह रचना की थी। भारत को तोड़ने के मंसूबे बना लिए थे लेकिन जब भारत ने ठोकना शुरू किया तो नवाज शरीफ अमेरिका के चरणों में लोट गए।

इतिहास के पन्ने तो पलट लिया करो मि. मुनीर, मसखरे जैसी हरकत से अपने देश की जग हंसाई क्यों कराते हो? मैं कई बार पाकिस्तान आया हूं, विदेशों में भी मुझे पाकिस्तानी लोग मिलते हैं। आपकी अवाम बड़ी प्यारी है, उन्हें क्यों धोखा दे रहे हो? जंग करनी है तो खुद की बेईमानी और जाहिलपने से करो। जंग गरीबी से करो ताकि अवाम को कम से कम आटा, दाल और तेल तो मिल जाए। भारत के खिलाफ आग उगलने से पाकिस्तानी अवाम की जिंदगी नहीं सुधरेगी। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की हरकतों का दुष्परिणाम है कि पाकिस्तानी मरीज अपना इलाज के लिए भारत नहीं आ पा रहे हैं, इलाज कराने क्या उन्हें अमेरिका भेजोगे? और जहां तक मशहूर उद्योगपति मुकेश अंबानी को आपकी धमकी का सवाल है तो मुझे बड़े-बुजुर्गों की कही एक बात याद आ रही है कि आदमी को अपनी औकात में रहना चाहिए। मुकेश अंबानी पर टिप्पणी से पहले एक बार खुद की हैसियत तो देख लेते। एक बार यह तो जान लेते कि मुकेश अंबानी किस हैसियत के मालिक हैं, मुकेश अंबानी के बारे में कुछ नहीं पढ़ा हो तो चलो, मैं ही बता देता हूं, इस वक्त मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति 8.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। अब आप याद कीजिए 2024-25 के पाकिस्तानी सालाना बजट को जो भारतीय रुपयों में महज 4.5 लाख करोड़ का ही था। यानी पाकिस्तानी बजट से करीब दो गुना संपत्ति मुकेश अंबानी के पास है, हम भारतीय उन्हें एक व्यक्ति के रूप में नहीं देखते, बल्कि उन्हें अपने आप में संस्थाओं का समूह मानते हैं। हम भारतीय नाज करते हैं उन पर और आपको क्या लगता है मि. मुनीर? आपकी मिसाइलें जामनगर पहुंच जाएंगी और हम तमाशा देखते रहेंगे? हम वो बुरा हाल करेंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्यों ऐसा बड़बोलापन दिखाते हो? बड़बोलेपन से याद आया कि आपके मुल्क के एक मंत्री हुआ करते थे शेख रशिद जो फरमाते थे कि पाकिस्तान ने पाव-पाव भर के ऐसे परमाणु बम बना रखे हैं जो लोगों का धर्म देखकर निशाना बनाएगा। कितने जाहिलपने की बात है ना। आजकल कहां हैं वो? खैर छोड़िए..! अपन तो आपकी बात करें, एक बार फिर परमाणु बम की जो धमकी आपने दी है, वह कुछ ऐसा ही है कि 'हम भी डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे' हमारे परमाणु बम हालांकि शांति के लिए हैं लेकिन एक बार यह तो सोच लेते कि भारत कितना विशाल है और पाकिस्तान कितना पिद्दी सा है। हम तो फिर भी कुछ न कुछ बचे रह जाएंगे। वहां क्या होगा कालिया।

कश्मीर में किताबों पर प्रतिबंध : सेंसरशिप या जवाबी कदम?

जब भारत सरकार ने हाल ही में जम्मू एवं कश्मीर में कथित रूप से आतंकवाद का महिमामंडन करने और अलगाववाद को उकसाने वाली 25 किताबों पर प्रतिबंध लगाया, तो प्रतिक्रियाएं एक चिर-परिचित पटकथा के अनुरूप ही सामने आईं सेंसरशिप के आरोप मढ़े गए, असहमति को दबा दिए जाने का डर जताया गया और असहज लगने वाले इतिहास को मिटा दिए जाने की चिंता जाहिर की गई लेकिन इन तमाम नारेबाजियों के परे एक गहरा सवाल है- उस संघर्ष में साहित्य की क्या भूमिका है, जहां खुद कहानियां ही अरसे से एक औजार बनी हुई हों? इस विवाद की जड़ें 1947 तक जाती हैं। पाकिस्तान के आधिकारिक इतिहास में, जम्मू एवं कश्मीर के भारत में विलय से पहले पाकिस्तानी सेना द्वारा समर्थित कबाइली हमले को कम करके दिखाया गया है। तब से राज्य समर्थित संदेशों की एक धारा-1990 के दशक में मारे गए आतंकवादियों की प्रशंसा करने वाले रेडियो पाकिस्तान के प्रसारणों से लेकर हाल के वर्षों में आईएसआई द्वारा वित्तपोषित सोशल मीडिया पर चलने वाले अभियानों तक ने कश्मीर को विभाजन के एक अधूरे मसले के रूप में पेश करने की कोशिश की है। भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की खोजबीन में कश्मीर के अलगाववादी समूहों को पाकिस्तान से धन मिलने का पता चला है, जिसका इस्तेमाल विरोध-प्रदर्शनों, प्रकाशनों और लोगों को लामबंद करने के अभियानों में किया जाता है। इस धन के अधिकांश हिस्से का उपयोग अकादमिक या सांस्कृतिक कार्यों की ओट में किया गया है, जिसकी बुनियाद पर ही किताबों पर लगाए गए हालिया प्रतिबंधों को उचित ठहराया गया है। इन प्रतिबंधित 25 कृतियों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर लेखकों की रचनाएं भी शामिल हैं। अरुंधति रॉय की 'आजादी' कश्मीर में भारत की सुरक्षा संबंधी मौजूदगी को औपनिवेशिक करार देती है लेकिन हथियारबंद उग्रवाद को बरकरार रखने में पाकिस्तान की भूमिका के बारे में शायद ही कोई बात करती है। हफ्सा कंजवाल की 'कोलोनाइजिंग कश्मीर' नाम की किताब कश्मीर को -उपनिवेशवादी बस्ती- के खांचे में रखती है तथा इसका मिलान इजरायल और फिलिस्तीन जैसी स्थिति से करती है जबकि आलोचकों का तर्क है कि यह किताब 1947 में हुए विलय के कानूनी आधार और बड़े पैमाने पर राज्य-प्रायोजित बसावट के अभाव को नजरअंदाज करती है। क्रिस्टोफर स्नेडेन की 'इंडिपेंडेंट कश्मीर' अलगाव को एक राजनीतिक विकल्प के रूप में देखती है। इसके बारे में भारतीय अधिकारियों का तर्क है कि यह किताब अलगाववादी नजरिए को बौद्धिक विश्वसनीयता प्रदान करती है। विदेशों में होने वाली अकादमिक और नीतिगत बहसों में उद्धृत की जाने वाली ये कृतियां, वैश्विक स्तर पर प्रचारित उस कथानक को मजबूत करने में मदद करती हैं, जिसमें भारत को हमलावर, पाकिस्तान को पीड़ित तथा हथियारबंद समूहों को स्वतंत्रता सेनानी के रूप में पेश किया जाता है। नेरेटिव दुष्प्रचार के जोखिम अमूर्त और बेमतलब नहीं हैं। वर्ष 1989 से अब तक कश्मीर में 40,000 से अधिक जानें जा चुकी हैं और आतंकवादियों की भर्ती अक्सर वैचारिक सामग्री से जुड़ी रही है।

नोट कीजिए, सरकार-जी के भाषण की अच्छाइयां

डॉ. द्रोण कुमार शर्मा

पिछले शुक्रवार स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ थी, पंद्रह अगस्त को। उस दिन सरकार जी ने देश की जनता को भाषण पिलाया। यह जो पंद्रह अगस्त को भाषण देने की एक प्रथा है वह शुरू से ही चली आ रही है। किसी भी सरकार जी ने, चाहे वह कितना भी साहसी, कितना भी महान रहा हो, इस प्रथा को तोड़ा नहीं है। जो लोग यह मानते हैं कि हमें स्वतंत्रता 1947 में नहीं, 2014 में मिली थी, वे लोग भी स्वतंत्रता दिवस पंद्रह अगस्त को ही मनाते हैं। उसी दिन भाषण देते और सुनते हैं। मैंने इस बार के सरकार जी के भाषण में बहुत सी अच्छाइयां ढूंढी हैं। मित्रों को मुझसे शिकायत रहती है कि मैं सरकार जी की कमियां ही ढूंढता हूं। जो व्यक्ति इतने साल से देश का सरकार जी है, जिसकी लोकप्रियता विश्व में नंबर एक पर बताई जाती है, जिसके विदेश दौरे पर देवियां फूट फूट कर रो पड़ती हैं, जो अपनी मां की मृत्यु होते ही अपने को नॉन बायोलॉजिकल घोषित कर देता है, उसमें कोई न कोई अच्छाई तो होगी ही। तो मैंने सरकार जी के इस भाषण में अच्छाइयां ही अच्छाइयां ढूंढी हैं। और मैंने पाया कि सरकार जी के भाषण में तो सारी की सारी बातें अच्छी हैं। कोई बुरी बात है ही नहीं। वही कहावत है ना, अच्छा जो देखन मैं चला... सबसे पहली अच्छी बात तो यह कि सरकार जी ने रिकॉर्ड तोड़ा। स्वतंत्रता दिवस पर किसी भी सरकार जी द्वारा दिये गए भाषण की लम्बाई का रिकॉर्ड। तोड़ने के लिए एक ही चीज सबसे अच्छी है, और वह है रिकॉर्ड। नेहरू, इंदिरा जी या मनमोहन सिंह के भाषण का रिकॉर्ड नहीं। उनके रिकॉर्ड तो सरकार जी पहले ही तोड़ चुके हैं। सरकार जी ने तो अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ा है। सरकार जी इस बार सौ मिनट की सीमा को पीछे छोड़ गए और एक सौ तीन मिनट लम्बा भाषण दिया। यह ऐतिहासिक था। देश के इतिहास में किसी सरकार जी ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में सौ मिनट की रेखा को पहली बार पार किया। इस एक सौ तीन मिनट लम्बे भाषण के कई लाभ हुए। सबसे बड़ा लाभ तो यह हुआ कि लोगों की एकाग्रता बढ़ी। ऐसे समाज में जहां लोग दस पंद्रह मिनट टिक कर नहीं बैठ सकते हैं, वहां हज़ारों लोगों को लाल किला मैदान में मंच के सामने पौने दो घंटे लम्बा भाषण सुनाना, लोगों की एकाग्रता बढ़ाने का ही काम था। इतना लम्बा भाषण सुनना सचमुच में तपस्या ही है। स्कूली बच्चे भी, पौने दो घंटे के भाषण के लिए, तीन चार घंटे बैठे रहें, इससे वे धैर्यवान ही बनते हो हैं। वैसे तो घर पर टीवी के सामने बैठ कर देखना, रेडियो के सामने बैठ कर सुनना भी तो आपके धैर्य की परीक्षा ही है। पर घर में यह स्वतंत्रता तो होती ही है कि आप पानी, चाय, कॉफ़ी पी सकते हैं। जा कर शंका निवारण कर सकते हैं पर वहां सामने बैठे हजारों लोगों को यह स्वतंत्रता भी नहीं थी। इस भाषण में सबसे अच्छी बात यह रही कि सरकार जी ने इस भाषण में जो भी वायदे किए, उनकी कोई समय सीमा नहीं रखी। सरकार जी समझदार हो गए हैं। समझ चुके हैं कि कोई भी काम समय सीमा में रख कर करना नितांत ही बेवकूफी है। चाहे स्मार्ट सिटी हो या बुलेट ट्रेन, चाहे किसानों की दुगनी आय हो या हर साल की दो करोड़ नौकरियां, जब कुछ भी समय पर पूरा नहीं हुआ तो आगे आने वाले वायदे कैसे पूरे होंगे। तो सरकार जी ने अच्छा किया कि देश के विकास को, देश की उन्नति को समय सीमा में नहीं बांधा। तो इस बार जो भी वायदे किए उनकी कोई समय सीमा नहीं निश्चित की। सरकार जी ने कहा कि निजी क्षेत्र साढ़े तीन करोड़ नौकरियां देगा। नौकरियों के बारे में सरकार जी का विज़न बहुत स्पष्ट रहा है। शुरू से ही रहा है। पहले कहते थे, मैं हर साल दो करोड़ नौकरियां दूंगा। वह नहीं हो पाया तो कहने लगे, पकौड़े तलना भी रोजगार है। उन्हीं दिनों पंक्चर लगाने को भी रोजगार माना गया पर वह अलग संदर्भ में माना गया। उसके बाद जनता से कहा गया कि नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो। सरकार तो नौकरी देने वाली बन नहीं रही है, जनता ही बन जाये। और अब कह रहे हैं कि निजी क्षेत्र नौकरी देगा। कब तक देगा, कैसे देगा, यह स्पष्ट नहीं है। यह सरकार जी की अच्छाई ही है कि सरकार जी नौकरी के बारे में अपने बदलते विचारों को किसी से छिपाते नहीं हैं। सरकार जी ने अपने इस भाषण में एक और अच्छी बात की।

जहां तक मैं देख, सुन, पढ़ पाया, सरकार जी ने इस भाषण में एक भी बार नेहरू को दोष नहीं दिया। इस मामले में सरकार जी पहली बार आत्मनिर्भर लगे। सरकार जी ने पहली बार नेहरू, कांग्रेस या अन्य किसी विपक्षी दल का नाम लिए बिना इतना लम्बा बोला। नहीं तो सरकार जी नेहरू जी या फिर विपक्षी दलों को दोष दिये बिना दो मिनट भी नहीं बोल पाते हैं। इस स्वतंत्रता दिवस पर सरकार जी नेहरू जी के प्रेत से मुक्त हो गए, यह इस भाषण की उपलब्धि है। इस स्वतंत्रता दिवस पर सरकार जी ने बहुत साहस दिखाया। नहीं, नहीं, मैं ऑपरेशन सिंदूर की बात नहीं कर रहा हूं। सरकार जी ने यह स्वीकार करने का साहस किया कि देश में महंगाई बढ़ रही है। इसीलिए उन्होंने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में कहा कि महंगाई कम करने के लिए जीएसटी कम किया जायेगा। लेकिन कब? कहा नहीं। यह काम अभी नहीं, दिवाली के आस पास किया जायेगा। हाँ, यह जरूर है कि सरकार जी ने यह नहीं बताया है कि यह काम इसी दिवाली को किया जायेगा या फिर अगली किसी दिवाली को। हो सकता है इस मामले में सरकार जी जब दीवाली की बात कर रहे हैं तो 2047 की दिवाली की बात कर रहे हों। स्वतंत्रता दिवस पर दिये गए भाषण में सरकार जी ने और भी अधिक साहस का काम किया है। लालकिले की प्राचीर से, स्वतंत्रता दिवस के भाषण में पहली बार किसी सरकार जी ने किसी ऐसे संगठन की प्रशंसा की है जिस पर राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की हत्या में लिप्त रहने का आरोप लग चुका है। जिस पर आज़ाद भारत की तत्कालीन सरकारें ही तीन तीन बार प्रतिबंध लगा चुकी हैं। जिसके बारे में यह माना जाता है कि उसका भारत के स्वतंत्रता संग्राम में तनिक भी योगदान नहीं रहा है। जिस पर देश के साम्प्रदायिक सद्भाव को नष्ट करने का आक्षेप लगता रहा है।

ऐसे संगठन की प्रशंसा करने का साहस सरकार जी स्वतंत्रता दिवस के अपने बारहवें सम्बोधन में जुटा सके, जो बहुत ही प्रशंसनीय है। सरकार जी ने भाषण तो बहुत लम्बा दिया। पर यह तो जरूरी नहीं है कि मैं भी उनकी प्रशंसा में उतना ही लम्बा व्यंग्य लिखूं। लम्बा लिखूंगा तो मेरे पाठक उकता जायेंगे। उनके धैर्य की परीक्षा हो जाएगी जिसके मूड में मैं बिल्कुल भी नहीं हूं। वे व्यंग्य पढ़ना छोड़, कुछ और करने बैठ जायेंगे। हालांकि सरकार जी की प्रशंसा के लिए अभी तो बहुत कुछ बाकी है पर मैं तो अपना यह व्यंग्य यहीं समाप्त करता हूं।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने वन्दना ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, साउथ पंचशील एक्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2010/...)

पशुपालन स्थाई समिति के बैठक में भाग लेंगे पीएन पाठक

कसया कुशीनगर ।

20 अगस्त को पशु पालन स्थाई समिति की बैठक लखनऊ में पशुपालकों की बात रखने का प्रयास किया जायेगा - पीएन पाठक

लखनऊ में 20 अगस्त को पशु धन मंत्री के अध्यक्षता में होने वाले पशु पालन स्थाई समिति के बैठक में भाग लेने के कुशीनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक पीएन पाठक को देवेन्द्र कुमार पाण्डेय विशेष सचिव का पत्र मिला है बता दें कि उक्त बैठक में 16 सदस्यीय टीम का गठन पशु पालन विभाग के द्वारा किया गया है जिसमें कुशीनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक पीएन पाठक को भी बैठक में भाग लेने के लिए विशेष सचिव देवेंद्र कुमार पांडेय का पत्र मिला है बैठक में भाग लेने के लिए विधायक पीएन पाठक जाते वक्त एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कहा कि बैठक में कुशीनगर के पशुपालकों के लिए एक योजना बनाकर काम करने की बात रखेंगे और पशुपालकों के अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात रखी जाएगी कुशीनगर में पशुओं को हो रही बिमारी से बचने हेतु अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात रखेंगे और पशुपालकों के लिए अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात रखने का प्रयास किया जायेगा।

जिला स्तरीय हाकी प्रतियोगिता 29 को

कुशीनगर। क्रीड़ अधिकारी रवि कुमार निषाद ने बताया कि खेल निदेशालय उत्तरप्रदेश एवं जिला खेल कार्यालय,स्पोर्ट्स स्टेडियम- कुशीनगर के तत्वावधान में हॉकी के जादूगर स्व0 मेजर ध्यानचन्द्र के जन्मदिन को खेल दिवस के रूप में मनाया जाना है। उक्त खेल दिवस के उपलक्ष्य में दिनांक 29 अगस्त,2025 को 14 वर्षीय बालकों की जिला स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन स्पोर्ट्स स्टेडियम-कुशीनगर के खेल ग्राउण्ड में प्रातः 10:00 बजे से किया जायेगा। इस प्रतियोगिता में प्रत्येक प्रतिभागी को अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य से आयु प्रमाण-पत्र एव आधार कार्ड की छाया प्रति साथ में लाना अनिवार्य है। प्रतियोगिता में टीमों को आने-जाने का किसी भी प्रकार का यात्रा- भत्ता देय नही है। प्रतियोगिता में विजेता एवं उपविजेता टीमों को एवं निर्णायकों को खेल विभाग द्वारा आकर्षक पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया जायेगा। उन्होंने जनपद कुशीनगर के जूनियर / हाईस्कूल के प्रधानाचार्यगण एवं हॉकी क्लबों / संस्थाओं से अनुरोध किया है कि आप अपने-अपने विद्यालयों/ क्लबों से 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बालकों की हॉकी टीम को आयु प्रमाण-पत्र के साथ निर्धारित तिथि व समय एवं स्थल जिला खेल कार्यालय,स्पोर्ट्स स्टेडियम- कुशीनगर के खेल,मैदान पर भेजने का कष्ट करें।

अनियंत्रित मोटरसाइकिल पोल में टकराई मौत

कप्तानगंज कुशीनगर। स्थानीय थाना क्षेत्र के ग्राम सभा पटखौली के सामने सुधियानी की तरफ से तरफ से आ रही मोटरसाइकिल सवार अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पोल में टकरा गए जिससे वह मौके पर गंभीर रूप से घायल हो गए,जिसको स्थानीय लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाएं जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बीती रात बसहिया उर्फ कप्तानगंज निवासी विनोद पुत्र स्वर्गीय रामाश्रय प्रसाद उम्र 22 वर्ष सुधियानी गांव में किसी काम से गए थे, वापस आते समय पटखौली गांव के सामने सड़क के किनारे सटे पोल में टकरा गए। जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। चीख की आवाज सुनकर अगल-बगल के लोग इकट्ठा हो गए और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाएं जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार शिविर का हुआ आयोजन

नेबुआ नौरंगिया, कुशीनगर। नेबुआ नौरंगिया विकास खण्ड स्थित बभनौली ग्रामसभा में सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेज के प्रबंध निदेशक पवन दूबे जी के नेतृत्व में आमजन हेतु निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार शिविर का आयोजन किया गया। इस हेल्थ कैंप में आजमगढ़ मेडिकल कॉलेज के पूर्व चिकित्सक डॉ.धनंजय कुमार सिंह की देखरेख में ग्रामीण अंचल के जरूरतमंद व्यक्तियों को निःशुल्क परामर्श, परीक्षण एवं दवा उपलब्ध कराई गई। शिविर में 315 व्यक्तियों ने उपचार हेतु पंजीकरण कराकर विशेषज्ञ चिकित्सक से परामर्श लिया। इस अवसर पर आमजन की विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का निदान किया गया। इस हेल्थ कैंप का उद्घाटन ग्राम प्रधान श्री राजेश जायसवाल द्वारा किया गया। इस अवसर पर सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेज के प्रबंध निदेशक पवन दूबे जी ने आगंतुक सभी व्यक्तियों के लिए जलपान का भी प्रबंध कराया था।

कोविड में अनाथ हुए बच्चों से डीएम दिव्या मित्तल का संवाद, कहा- आप अकेले नहीं हैं

देवरिया।

कलेक्ट्रेट स्थित एन.आई.सी. सभागार मंगलवार को उस समय बेहद संवेदनशील और आत्मीय माहौल का साक्षी बना जब जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने 'पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन योजना' से आच्छादित बच्चों के साथ सीधा संवाद किया। कोरोना काल में अपने माता पिता को खो चुके इन मासूमों से जब जिलाधिकारी ने एक एक कर उनका नाम, शिक्षा, निवास और भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछा, तो बच्चों ने निर्भीक होकर अपनी बात रखी। इसी क्रम में एक बालिका ने जिलाधिकारी के समक्ष कहा कि वह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहती है। यह सुनकर पूरे सभागार का माहौल भावुक हो उठा। जिलाधिकारी ने बच्चों से शिक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्वास, पैतृक संपत्ति की सुरक्षा और उनके रोजमर्रा के हालात पर विस्तार से बातचीत की। उन्होंने नोडल अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि बच्चों से जुड़ी हर जानकारी को चेकलिस्ट के आधार पर मासिक रूप से संकलित करें और त्रैमासिक फील्ड विजिट के बाद विस्तृत आख्या जिला बाल संरक्षण इकाई को उपलब्ध कराएं। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने बच्चों को भरोसा दिलाया कि आपकी किसी भी समस्या को अनदेखा नहीं किया जाएगा। आप सीधे संरक्षण अधिकारी या जिला बाल संरक्षण इकाई से संपर्क करें, हर संभव निस्तारण होगा। आप अकेले नहीं हैं, पूरा प्रशासन आपके साथ खड़ा है। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी प्रत्यूष पांडेय ने बच्चों को स्वास्थ्य सुरक्षा के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि भारत सरकार ने उन्हें आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराया है, जिसका आवश्यकतानुसार उपयोग किया जाए। कार्यक्रम का संचालन करते हुए जिला परिवीक्षा अधिकारी अनिल कुमार सोनकर ने योजना के महत्व और बच्चों को मिलने वाले लाभों पर प्रकाश डाला।

वहीं, संरक्षण अधिकारी (जिला बाल संरक्षण इकाई) जयप्रकाश तिवारी ने योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उन बच्चों के लिए चलाई गई है जिनके माता-पिता या वैधानिक अभिभावक की मृत्यु 11 मार्च 2020 से 31 दिसंबर 2021 के बीच कोविड-19 से हुई हो। उन्होंने बताया कि इस योजना में प्रत्येक पात्र बच्चे के लिए वित्तीय प्रावधान किया गया है, जिसके तहत उनकी आयु 18 वर्ष पूरी होने तक राशि जोड़कर 10 लाख रुपये होगी। यह धनराशि बच्चों को 23 वर्ष की आयु पर उपलब्ध कराई जाएगी।

साथ ही 18 से 23 वर्ष की उम्र तक उन्हें हर वर्ष स्टाइपेंड मिलेगा। जनपद में वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत 01 बालक और 08 बालिकाएं आच्छादित हैं। इन बच्चों की देखरेख की जिम्मेदारी प्रशासन ने विभाजित करते हुए उप जिलाधिकारी रुद्रपुर, तहसीलदार सलेमपुर, खंड शिक्षा अधिकारी सलेमपुर, खंड शिक्षा अधिकारी रामपुर कारखाना, खंड शिक्षा अधिकारी देवरिया सदर और जिला परिवीक्षा अधिकारी कुशीनगर को सौंपी है। इस अवसर पर मुख्य डाक अधीक्षक राजकुमार, विनय कुमार शर्मा (संरक्षण अधिकारी, जिला बाल संरक्षण इकाई कुशीनगर), खंड शिक्षा अधिकारियों के प्रतिनिधि, साथ ही जिला प्रोबेशन कार्यालय से सैफ खान (कनिष्ठ सहायक) एवं जिला बाल संरक्षण इकाई के जैनेंद्र पांडेय (ओआरडब्ल्यू) सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

बेरोजगार अभ्यर्थी रोजगार संगम पोर्टल पर कराएं पंजीकरण : डीएम

कुशीनगर।

जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में उत्तरप्रदेश रोजगार मिशन के अन्तर्गत गठित जिला कार्यकारी समिति की प्रथम बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गयी। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि सेवायोजन विभाग द्वारा संचालित रोजगार संगम पोर्टल पर जनपद के बेरोजगार अभ्यर्थी, कुशल श्रमिक औद्योगिक संस्थान / ईकाई एवं अन्य नियोजक का पंजीकरण क्रमशः जॉबसीकर एवं नियोजक के रूप में कराना है। रोजगार संगम पोर्टल पर बेरोजगार अभ्यर्थी एवं नियोजक निम्न प्रक्रिया अपना कर अपना पंजीकरण स्वयं किसी निकट के जन सुविधा केन्द्र अथवा साइबर कैफे से कर सकते है।

यूपी-बिहार बॉर्डर पर ताबड़ तोड़ छापेमारी: 292 लीटर अंग्रेजी शराब के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

नेबुआ नौरंगिया, कुशीनगर । पिछले दो दिनों से यूपी-बिहार बॉर्डर पर दो राज्यों की पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। यह कार्रवाई शराब तस्करों की तलाश में यूपी और बिहार की पुलिस कर रही है। इस कार्रवाई के तहत बॉर्डर पर सोमवार की सुबह करीब 6 बजे बिहार पुलिस ने 292 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद करते हुए दो तस्करों को गिरफ्तार भी कर लिया है। इसे लेकर अंतरराज्यीय सीमा पर शराब की तस्करी करने वाले तस्करों खलबली मची हुई है। गंडक नदी के रास्ते उत्तर प्रदेश से बिहार में धड़ल्ले से हो रही शराब तस्करी को रोकने के लिए कुशीनगर पुलिस ने एक विशेष टीम का गठन किया है, वहीं बिहार मद्य निषेध विभाग ने भी दो अलग-अलग टीमों को निगरानी का जिम्मा सौंपा है। विभागीय अधिकारियों को आशंका थी कि खुलासे के बाद तस्कर रास्ता बदल देंगे और सोमवार की सुबह ऐसा ही हुआ। 292 लीटर शराब बरामद,बगहा जिले की मद्य निषेध विभाग की टीम ने बांसी चौकी के समीप चेक पोस्ट पर चेकिंग के दौरान एक एसयूवी कार से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की। थानाध्यक्ष सह निरीक्षक प्रमोद कुमार ने बताया कि वाहन रोककर तलाशी लेने पर उसमें से 34 पेटी यानी लगभग 292 लीटर अंग्रेजी शराब मिली। मौके से दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया। उनकी पहचान मुन्ना कुमार (23 वर्ष) पुत्र लखींद्र महतो निवासी थाथन बुजुर्ग थाना हाजीपुर, जिला वैशाली और निखिल ठाकुर (20 वर्ष) पुत्र मनोज ठाकुर निवासी असावरपुर थाना हाजीपुर, जिला वैशाली के रूप में हुई है। गिरफ्तारी करने वाली टीम में थानाध्यक्ष सह निरीक्षक प्रमोद कुमार, एएसआई तारणी प्रसाद, एएसआई भगवान शर्मा, सिपाही ह्रशिम आलम और अमित कुमार शामिल रहे। अधिकारियों का कहना है कि शराब तस्करी के खिलाफ अभियान और भी तेज किया जाएगा।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आर.पी.एम. स्कूल के बच्चों को दी गई कृमि नियंत्रक दवा

भटनी देवरिया । दिन मंगलवार को भटनी नगर के हरिकीर्तन मोहल्ला स्थित आर.पी.एम. स्कूल में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 3 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को कृमि नियंत्रक दवा (ऐलबैण्डाजोल) खिलाई गई। इस अवसर पर कार्यक्रम के संयोजक डॉ. अनिल पाण्डेय (पूर्व स्वास्थ्य निरीक्षक, वर्तमान आशा प्रशिक्षक देवरिया), सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मी एस.एन. कुशवाहा (एन.एम.ए) तथा बी.सी.पी.एम. श्रीमती रानी यादव उपस्थित रहीं। इन्होंने बच्चों को दवा खिलाई और कृमि से होने वाले नुकसान एवं दवा के महत्व के बारे में जानकारी दी। विद्यालय के संरक्षक प्रभुनाथ मिश्रा तथा शिक्षक-शिक्षिकाएँ श्रीमती नीलम तिवारी, सरोज पटेल, मनीष मिश्रा, भूपेंद्र कुशवाहा, रिंकि बरनवाल सहित अन्य स्टाफ एवं अभिभावक भी इस अवसर पर मौजूद रहे।

राज्यसभा में उठा खनन सुधार का मुद्दा, खनिज और खदान संशोधन विधेयक पर गरमाई बहस

नई दिल्ली। राज्यसभा में मंगलवार को खनिज और खदान (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025 पर चर्चा शुरू हुई। यह विधेयक देश में खनन से जुड़े नियमों को आसान बनाने और खासतौर पर महत्वपूर्ण खनिजों के खनन के लिए नई व्यवस्था तैयार करने का लक्ष्य रखता है। यह विधेयक पहले ही लोकसभा से पारित हो चुका है और अब ऊपरी सदन में विचार के लिए लाया गया। विपक्ष ने इस दौरान बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण का मुद्दा उठाने की कोशिश की, लेकिन सभापति घनश्याम तिवारी ने स्पष्ट कर दिया कि सदन में केवल इस विधेयक पर चर्चा होगी। इसके बाद विपक्ष ने नारेबाजी की और वॉकआउट कर दिया। कोयला एवं खनन मंत्री जी. किशन रेड्डी ने विधेयक को सदन में पेश करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में खनन क्षेत्र में काफी बदलाव आया है और यह संशोधन आगे और सुधार लाएगा। उन्होंने कहा कि चाहे खनिज ब्लॉकों की नीलामी हो या खोज कार्य, यह विधेयक देश में एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला तैयार करेगा। मंत्री ने बताया कि स्वतंत्रता के बाद 2015 तक खनिजों की खोज ठीक से नहीं हो पाई थी। केवल भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग इस कार्य को करता था। 2015 में नेशनल मिनरल डेवलपमेंट एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट बनाया गया और अब इस विधेयक से और पारदर्शिता आएगी। विधेयक पेश होने पर सीपीआई(एम) सांसद जॉन ब्रिटास ने आपत्ति जताई और कहा कि यह राज्यों के अधिकारों का उल्लंघन करता है। उन्होंने दलील दी कि भूमि राज्य का विषय है, इसलिए केंद्र को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। एआईएडीएमके सांसद एम. थंबीदुरई ने भी इसी मुद्दे को उठाया और कहा कि यह विधेयक राज्यों के अधिकारों पर असर डालेगा। हालांकि, विपक्ष की आपत्तियों को सदन की कुर्सी ने खारिज कर दिया।

समर्थन और आलोचना दोनों

भाजपा सांसद भीम सिंह ने विधेयक को सरकार के सुधारों की एक और कड़ी बताया। वाईएसआर कांग्रेस के सांसद अयोध्या रामी रेड्डी ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि यह विधेयक जरूरी खनिजों की खोज और उत्पादन को बढ़ावा देगा, जिससे भारत आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को हासिल कर सकेगा। बीजू जनता दल के सांसद मानस रंजन मंगराज ने हालांकि चिंता जताई कि इस विधेयक में खनन से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान को दूर करने का कोई ठोस प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि ओडिशा जैसे राज्यों में खनिज संपदा वरदान की बजाय अभिशाप साबित हो रही है। खनन से प्रदूषण और क्षति बढ़ रही है, लेकिन इन जिलों को उनका उचित हिस्सा नहीं मिल रहा।

भारत की आत्मनिर्भरता के लिए अहम कदम

शिंदे वाली शिवसेना के सांसद मिलिंद देवड़ा ने इस विधेयक को भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ खनन नीति में सुधार नहीं है बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक रणनीतिक आवश्यकता है। कुल मिलाकर, खनिज और खदान संशोधन विधेयक, 2025 को लेकर संसद में सियासी घमासान देखने को मिला।

सुदर्शन रेड्डी होंगे उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार; राधाकृष्णन को देंगे चुनौती

नई दिल्ली। पूर्व न्यायाधीश जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इनके नाम का एलान किया। उन्होंने बताया कि विपक्ष ने एकमत होकर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के नाम पर सहमति जताई है। इससे पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं ने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम पर फैसला लेने और उसकी घोषणा करने के लिए 10 राजाजी मार्ग पर बैठक की थी। बैठक के बाद विपक्ष ने उनके नाम का एलान किया। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी 21 अगस्त को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, बी. सुदर्शन रेड्डी भारत के सबसे प्रतिष्ठित और प्रगतिशील न्यायविदों में से एक हैं। उनका एक लंबा और प्रतिष्ठित कानूनी करियर रहा है। वे आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, गौहाटी उच्च न्यायालय के

मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम कर चुके हैं। वे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के एक निरंतर और साहसी समर्थक रहे हैं। वे एक गरीब हितैषी व्यक्ति हैं। यदि आप उनके कई फैसले पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने कैसे गरीबों का पक्ष लिया और संविधान व मौलिक अधिकारों की रक्षा की।

राजग के सीपी राधाकृष्णन से मुकाबला

पूर्व न्यायाधीश जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी का मुकाबला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से होगा। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है, जो आरएसएस पृष्ठभूमि वाले तमिलनाडु के एक अनुभवी भाजपा नेता हैं। विपक्षी गठबंधन की ओर से अपने नाम का एलान किए जाने के बाद उन्होंने कहा कि मैं सभी दलों से समर्थन की अपील करता हूं। तृणमूल कांग्रेस नेता डेरेक ओब्रायन के अनुसार, आम आदमी पार्टी (आप) भी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए रेड्डी का समर्थन कर रही है।

कौन हैं जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी?

जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी का जन्म 8 जुलाई, 1946 को अकुला मायलाराम गांव, पूर्व इब्राहिमपट्टनम तालुका, रंगारेड्डी (आंध्र प्रदेश) में हुआ था। उनका नाता वर्तमान में कंदुकुर राजस्व मंडल के तहत आने वाले गांव के एक कृषक परिवार से रहा। उन्होंने हैदराबाद में पढ़ाई की और 1971 में उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद से कानून की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने 1971 में ही अधिवक्ता के रूप में अपनी पहचान बना ली। इसके बाद वे वरिष्ठ अधिवक्ता के. प्रताप रेड्डी के चैंबर में शामिल हुए। उन्होंने हैदराबाद के नगर दीवानी न्यायालयों के साथ-साथ आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में कई मामलों का निपटारा किया। वे 8 अगस्त, 1988 को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में सरकारी वकील के रूप में नियुक्त हुए। वे राजस्व विभाग के प्रभारी भी रहे और 8 जनवरी, 1990 तक इस पद पर बने रहे। इसके बाद वे कुछ समय के लिए केंद्र सरकार के अतिरिक्त स्थायी वकील के रूप में भी नियुक्त हुए। जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी एवी एजुकेशन सोसाइटी की ओर से संचालित शैक्षणिक संस्थानों के सचिव और संवाददाता भी रहे। 1993-94 के लिए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष चुने गए। 8 जनवरी, 1993 को उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद के कानूनी सलाहकार और स्थायी वकील नियुक्त किए गए। 2 मई, 1995 से आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए गए। उन्हें 2005 में गौहाटी हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। 2007 में उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए। वे 2011 में सेवानिवृत्त हुए।

जे,जे, कॉलोनी में नाबालिग बच्चों का आतंक

नई दिल्ली (विजय कुमार भारती) बाहरी जिला सुल्तानपुरी में एक 24 वर्षीय युवक अजय कुमार पर कुछ नाबालिग लड़कों ने चाकू से हमला कर दिया। अजय को गंभीर हालत में संजय गांधी स्मारक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना ने एक बार फिर से नाबालिग अपराधियों के मुद्दे को उजागर किया है।

नाबालिग अपराध- एक बढ़ती समस्या

- दिल्ली में नाबालिग अपराधों की संख्या में वृद्धि हो रही है। 2021 में, दिल्ली में 3287 नाबालिगों को अपराधों के लिए पकड़ा गया था।
- इनमें से अधिकांश नाबालिग 16 से 18 वर्ष की आयु के बीच के थे।
- नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों में चोरी, डकैती, हत्या और अपहरण जैसे संगीन अपराध शामिल हैं।

नाबालिग अपराधों के कारण*

- पारिवारिक समस्याएं और आर्थिक संकट
- शिक्षा की कमी और बेरोजगारी
- सोशल मीडिया और फिल्मों का नकारात्मक प्रभाव
- नशीली दवाओं का सेवन और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं
- नाबालिग अपराधियों के लिए पुनर्वास और शिक्षा कार्यक्रम
- परिवारों और समुदायों में जागरूकता और समर्थन
- कानून और व्यवस्था को मजबूत करना और नाबालिग अपराधियों के लिए सजा को और कड़ा करना
- नाबालिगों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं और काउंसलिंग को बढ़ावा देना इस घटना ने एक बार फिर से नाबालिग अपराधों के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया है और समाज को इस समस्या का समाधान खोजने के लिए प्रेरित किया है

नेहरू ने देश को 2 बार बांटा, सिंधु जल संधि से नहीं हुआ कोई फायदा- मोदी

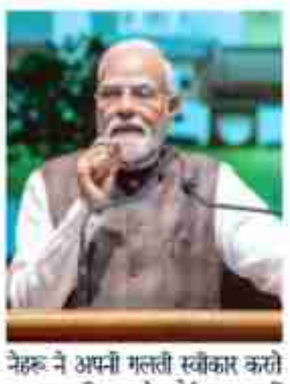

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की संसदीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकार किया था कि पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि से भारत को कोई लाभ नहीं हुआ। सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी ने कहा कि नेहरू ने देश का दो बार विभाजन किया था, एक बार रेडक्लिफ रेखा के साथ और दूसरी बार उस संधि के दौरान, जिसके तहत नदी का 80 प्रतिशत पानी पाकिस्तान को दे दिया गया था। पीएम मोदी ने कहा कि वह समझौता किसान विरोधी भी था। मोदी ने कहा कि नेहरू ने एक बार देश का विभाजन किया और फिर दोबारा। सिंधु जल संधि के तहत, 80 प्रतिशत पानी पाकिस्तान को दे दिया गया। बाद में, अपने सचिव के माध्यम से,

नेहरू ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा कि इससे कोई लाभ नहीं हुआ। बैठक में मौजूद भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर करने को नेहरू द्वारा विश्वासघात बताया और कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री को इसके लिए संसद की मंजूरी लेनी चाहिए थी। पाल ने एएनआई से कहा कि देश के साथ विश्वासघात हुआ है। अगर वह (जवाहरलाल नेहरू) लोकतांत्रिक चुनाव में प्रधानमंत्री होते, तो उन्हें इसके लिए संसद की मंजूरी लेनी चाहिए थी। कैबिनेट और संसद के विश्वास के बिना, वह पाकिस्तान गए और समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद अकेले वापस आ गए... यह हमारे किसानों के साथ विश्वासघात है। प्रधानमंत्री की टिप्पणी की सराहना करते हुए, भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने नेहरू के नेतृत्व वाली सरकार की पाकिस्तान को 80 करोड़ रुपये देने के लिए आलोचना की। भाजपा नेता ने कहा कि हमें गर्व है कि प्रधानमंत्री ने तथ्य बताए। नेहरू जी ने न केवल कैबिनेट की मंजूरी या चर्चा के बिना संधि पर हस्ताक्षर किए, बल्कि उन्हें 80 करोड़ रुपये भी दिए। जब भी किसी संधि पर हस्ताक्षर होते हैं, तो वह संसद में चर्चा के बाद ही होता है।

अगली बार राहुल गांधी को पीएम बनाएंगे : तेजस्वी

नवादा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मंगलवार को 'वोटर अधिकार यात्रा' के तहत नवादा जिले के हिसुआ, नवादा और वारिसलीगंज पहुंचे। गया-नवादा बॉर्डर (तुंगी) से प्रवेश करते ही महागठबंधन नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। नवादा के भगत सिंह चौक पर आयोजित जनसभा में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि एसआईआर के बहाने गरीबों के वोट काटे जा रहे हैं। चुनाव आयोग और भाजपा की साझेदारी से वोट चोरी हो रही है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि किसान सुबोध कुमार ने लोकसभा चुनाव में मतदान किया और पोलिंग एजेंट भी रहे, लेकिन अब उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि पहले आपका वोटर आईडी छीना जाएगा, फिर राशन कार्ड और अंत में जमीन। यह देश अडानी-अंबानी का नहीं, बल्कि किसानों और मजदूरों का

है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने मंगलवार को कहा कि अगले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए विपक्ष मिलकर काम करेगा। उनकी टिप्पणी से इस बात के स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि 2029 के आम चुनावों में राहुल गांधी को इंडिया ब्लॉक के प्रधानमंत्री पद के चेहरे के रूप में पेश किया जा सकता है। राजद नेता ने कहा कि अगले लोकसभा चुनाव होने पर हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की दिशा में काम करेंगे। बिहार के नवादा में मतदाता अधिकार रैली का नेतृत्व करते हुए, लोकसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की मौजूदगी में यादव ने यह टिप्पणी की। रैली को संबोधित करते हुए, यादव ने यह भी कहा कि अब समय आ गया है कि युवा पीढ़ी को राज्य चलाने का मौका मिले। यादव ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली

वोटर अधिकार यात्रा पहुंची नवादा, हिसुआ और वारिसलीगंज; राहुल और तेजस्वी ने चुनाव आयोग-बीजेपी पर बोला हमला

सरकार खटारा हो गई है और इसे तुरंत बदलने की जरूरत है। युवाओं को अब मौका मिलना चाहिए... हमारे पास बिहार के लिए एक विज़न है। युवाओं ने संकल्प लिया है कि वे इस पुरानी और जर्जर सरकार को सत्ता से हटाएंगे और अगले लोकसभा चुनावों के बाद राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारे पास बिहार के लिए दृष्टिकोण है। युवाओं ने संकल्प लिया है कि वे इस पुरानी और खटारा सरकार को सत्ता से हटाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि अगले लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनें। भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने भी इसपर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बिहार में मतदाता सूची की समीक्षा के कारण यह यात्रा चल रही है। इसलिए, राहुल गांधी ने वहाँ पहुँचते ही उन्हें (तेजस्वी यादव को) बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। क्या सिर्फ बातें करने से कोई फ़र्क़ पड़ता है?...मुझे लगता है कि यह उनकी बातें करने की कला है, आप इसे व्यंग्य भी कह सकते हैं...ये दोनों (टिप्पणियाँ) वास्तविकता से कोसों दूर हैं। यादव ने दोहराया कि बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) लोगों को उनके मताधिकार से वंचित करने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास है। उन्होंने कहा, एसआईआर वोटों की डकैती है और हम ऐसा नहीं होने देंगे। यह बिहार में मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने की सत्तारूढ़ दल की साजिश है।

मोहब्बत की दुकान नहीं, झूठ का शोरूम चला रहे, फर्जी वोटिंग के आरोपों पर बीजेपी ने राहुल को घेरा

मुंबई। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कथित फर्जी वोटिंग के आरोपों पर दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि याचिका में कोई ठोस सबूत नहीं है और यह कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। भाजपा नेता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी को घेरते हुए कहा कि वो मोहब्बत की दुकान नहीं, बल्कि झूठ का शोरूम चला रहे हैं। महाराष्ट्र में मतदाता डेटा को लेकर कांग्रेस द्वारा उठाए गए सवालों पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा नेता गौरव भाटिया ने कहा कि 40 घंटे तक झूठ फैलाकर लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की गई और चुनाव आयोग की साख पर सवाल उठाए गए। उन्होंने सवाल उठाया कि इस झूठ की जिम्मेदारी कौन लेगा और क्या राहुल गांधी इसके लिए देश से माफी मांगेंगे। भाटिया ने कहा कि जब इतनी देर तक झूठी जानकारी फैलाई गई तो उसे देखने वाले लोग इसे सच मान बैठे होंगे। उन्होंने कांग्रेस पर जनता के विश्वास को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह सीधे-सीधे लोकतंत्र पर हमला है। भाजपा का कहना है कि विपक्ष लगातार संस्थाओं को बदनाम करने की राजनीति कर रहा है, जबकि देश की जनता सच्चाई को समझती है और इस तरह की साजिशों को कभी स्वीकार नहीं करेगी।

महाराष्ट्र में आफत की बारिश, अब तक 14 लोगों की मौत सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले- अगले 48 घंटे बेहद अहम

मुंबई। महाराष्ट्र के कई जिलों में मंगलवार को तेज बारिश जारी है। पिछले दो दिनों में बारिश से जुड़े हादसों में 14 लोगों की मौत हो गई। अगले 48 घंटे मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिले में रेड अलर्ट है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि नांदेड़ में बादल फटने से 8 लोगों की मौत हो गई। सेना रेस्क्यू में जुटी है। करीब 500 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। मुंबई में करीब 300 एमएम बारिश हुई है। मीठी नदी का जलस्तर घट रहा है। हालांकि, अभी भी कई इलाकों में अलर्ट है। सुबह मीठी नदी का जलस्तर 3.9 मीटर बढ़ने के कारण कुर्ला क्रांति नगर एरिया से 350 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। शहर में आज भी स्कूल-कॉलेज, गवर्नमेंट और सेमी-गवर्नमेंट ऑफिस बंद हैं। 250 से

'मुंबई में लगातार बारिश से सड़कें डूबीं, घर-दुकानों में पानी
'लोकल ट्रेन सर्विस डाउन, 250 से ज्यादा फ्लाइट्स लेट

ज्यादा फ्लाइट देरी से उड़ रही हैं। अंधेरी सब-वे भी पानी भरने से आज भी बंद है। कई अंडर ब्रिज में 4 फीट तक पानी भरा है। लोकल ट्रेन सर्विस भी प्रभावित है। हार्बर लाइन का ट्रैक पानी में डूबा हुआ है। कुछ वीडियो सामने आए हैं, जिसमें लोग रेलवे ट्रैक पर चलते नजर आ रहे हैं।

हिमाचल में बादल फटा

इधर, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में सोमवार रात 1 बजे बादल फटा। तेज बहाव में 3 दुकानें बह गईं। भूतनाथ के पास ब्यास नदी के उफान पर होने के कारण सड़क का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। यहां पुल भी तेज बहाव में बहा है।

16 साल की मुस्लिम लड़की पर्सनल लॉ के तहत वैध विवाह की हकदार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी, जिसमें पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के 2022 के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें कहा गया था कि 16 साल की मुस्लिम लड़की किसी मुस्लिम पुरुष से वैध विवाह कर सकती है और जोड़े को धमकियों से सुरक्षा प्रदान की गई थी। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कहा कि एनसीपीसीआर इस मुकदमे से अनजान है और उसे उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है। पीठ ने पूछा

कि एनसीपीसीआर को धमकियों का सामना कर रहे दंपति के जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करने वाले उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती क्यों देनी चाहिए? पीठ ने कहा कि एनसीपीसीआर के पास ऐसे आदेश को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है... अगर दो नाबालिग बच्चों को उच्च न्यायालय द्वारा संरक्षण दिया जाता है,

एनसीपीसीआर की याचिका खारिज करते हुए उच्च न्यायालय ने सुनाया बड़ा फैसला

तो एनसीपीसीआर ऐसे आदेश को कैसे चुनौती दे सकता है। यह अजीब है कि एनसीपीसीआर, जिसका काम बच्चों की सुरक्षा करना है, ने ऐसे आदेश को चुनौती दी है। एनसीपीसीआर के वकील ने दलील दी कि वे कानून का सवाल उठा रहे थे कि क्या 18 साल से कम उम्र की लड़की को सिर्फ पर्सनल लॉ के आधार पर क़ानूनी तौर पर शादी करने की योग्यता दी जा सकती है। हालांकि, पीठ ने कहा कि इस मामले में कानून का कोई सवाल ही नहीं उठता। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने कहा कि कानूनी सवाल ही नहीं उठता। याचिका खारिज करते हुए पीठ ने अपने आदेश में कहा कि कृपया किसी उचित मामले में चुनौती दें। हम यह समझ नहीं पा रहे हैं कि एनसीपीसीआर ऐसे आदेश से कैसे असहमत हो सकता है। यदि उच्च न्यायालय, अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, दो व्यक्तियों को संरक्षण प्रदान करना चाहता है, तो एनसीपीसीआर को ऐसे आदेश को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है।

कोटा-बूंदी एयरपोर्ट को मंजूरी, कटक-भुवनेश्वर में बनेगा 6 लेन रिंग रोड

नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मंगलवार (19 अगस्त 2025) को कई बड़े फैसले लिए गए, मोदी सरकार ने राजस्थान के कोटा-बूंदी में 1507 करोड़ रुपये की लागत से नया हवाई अड्डा बनाने का एलान किया है. ओडिशा के कटक और भुवनेश्वर में सिक्स लेन एक्सेस-कंट्रोल्ड रिंग रोड बनाने की मंजूरी दी गई है. इस परियोजना पर 8,307 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

राजस्थान में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, कैबिनेट ने 1,507 करोड़ रुपये की

अनुमानित लागत से राजस्थान में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे- कोटा-बूंदी हवाई अड्डे के विकास को मंजूरी दे दी है. टर्मिनल भवन 3200 मीटर लंबे रनवे के साथ 20,000 वर्गमीटर क्षेत्र में फैला है. इसकी क्षमता प्रति वर्ष 20 लाख यात्रियों की होगी. 2 साल के अंदर इसे पूरा करने के लक्ष्य पर काम किया जा रहा है. उन्होंने कहा, -भारत में साल 2014 तक केवल 74 एयरपोर्ट थे. पिछले 11 सालों में यह संख्या दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है. अब भारत में 162 एयरपोर्ट एक्टिव हैं. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कोटा-बूंदी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण को लेकर कहा, कोटा एक इंडस्ट्रियल और एजुकेशन सेंटर है. शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोग नियमित रूप से कोटा आते हैं. यहां लंबे समय से एयरपोर्ट की मांग की जा रही थी. मौजूदा हवाई अड्डा पुराना है और इसे आधुनिकीकरण की आवश्यकता है.

ओडिशा को 6 लेन एक्सेस-कंट्रोल्ड रिंग रोड का तोहफा

केंद्रीय कैबिनेट ने ओडिशा में हाइब्रिड एन्युटी मोड पर 8,307.74 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले 6-लेन एक्सेस-कंट्रोल्ड कैपिटल रीजन रिंग रोड (भुवनेश्वर बाईपास - 110.875 किमी) के निर्माण को मंजूरी दी है. केंद्रीय मंत्री ने कहा, इस परियोजना को 6-लेन एक्सेस-कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड हाईवे के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है. इससे कटक, भुवनेश्वर और खोरधा शहर में रह रहे लोगों को बड़ा फायदा होगा.

ऐसे डबल इंजन पर धिक्कार है.., ट्रेन में ज्यादा लगेज पर जुर्माना लगाने की खबरों पर भड़के अखिलेश यादव

नई दिल्ली। भारतीय रेलवे के संदर्भ में दावा किया जा रहा है कि ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों को लेकर बड़ा बदलाव किया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब यात्रियों के लिमिट से ज्यादा लगेज ले जाने पर अतिरिक्त चार्ज देना होगा. हालांकि रेलवे ने ऐसे किसी फैसले के दावों को अफवाह बताया है. इस बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाए और कहा कि बीजेपी ने रेलवे को भी खोखला कर दिया है. सपा अध्यक्ष ने रेलवे के इस फैसले को लेकर निशाना साधते हुए एक्स पर पोस्ट किया. उन्होंने लिखा- भाजपा जनता के लिए भारी बोझ बन गयी है. जिस दिन भाजपाई भ्रष्टाचार की पोटली को जनता तोल देगी, उस दिन भाजपा पटरी से उतर जाएगी। और अब वो दिन बहुत दूर भी नहीं. कन्नौज सांसद ने लिखा कि रेल में यात्रियों के सामान को तोलने के नाम पर भ्रष्टाचार का एक और अध्याय खोला जा रहा है. ये फैसला गरीबों के खिलाफ है, जो ,एसी-1 में जा रहा है, उसे क्या फर्क पड़ता है लेकिन, उस गरीब से पूछो जो साल में एक-दो बार घर-गांव जाता है और वहां से अपने साथ दाल-चावल-राशन बांधकर लाता है. उन्होंने लिखा कि अब क्या गरीब मजदूर-किसान की थाली का खाना भी भाजपा छीन लेना चाहती है. पैसे की भूखी भाजपा को जो वसूलना है वो एसी-1 और एसी-2 तक के लोगों से वसूले न कि जनरल, स्लीपर या एसी-3 वालों से. अगर भाजपा सरकार के शासनकाल में रेलवे का खज़ाना पूरी तरह खाली हो गया है तो वो अपने सांसदों-विधायकों से कहे कि वो लोग अपने मुल्क के पास छोड़ दें.